www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 25 अगस्त 2019

दैनिक जागरण

किसी व्यक्ति के विचार और विरासत उसे अमरता प्रदान करते हैं

एक राजनेता का अवसान

पूर्व वित्त एवं रक्षा मंत्री अरुण जेटली का असमय निधन भाजपा के साथ-साथ देश की राजनीति के लिए भी एक बड़ी क्षति है। भाजपा को इस क्षति का आभास इसलिए और अधिक होगा, क्योंकि अभी चंद दिन पहले ही पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का निधन हुआ है। हालांकि न तो सुषमा स्वराज केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा थीं और न ही अरुण जेटली, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उनकी सक्रियता भाजपा के साथ ही भारतीय राजनीति को भी संबल प्रदान करती थी। भाजपा के उत्थान में दोनों का ही बराबर का योगदान रहा। एक समय था जब ये दोनों एक साथ सक्रिय और उपस्थित दिखते थे। यह विडंबना ही है कि समय के थोड़े से अंतराल में दोनों बारी-बारी से चल बसे। भाजपा के साथ भारतीय राजनीति को अरुण जेटली की कमी इसलिए महसूस होगी, क्योंकि वह अक्सर ही संकट मोचक की भूमिका में दिखते थे। वह नेता से अधिक रणनेता थे। वह जटिल से जटिल विषयों के जानकार ही नहीं थे, बल्कि उन्हें सरल तरह से व्यक्त करने में महारत रखते थे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि वह आम सहमति कायम करने में अग्रणी भूमिका निभाते थे। यदि जीएसटी जैसी जटिल व्यवस्था अमल में आ सकी तो इसका सबसे अधिक श्रेय अरुण जेटली को ही जाता है। अलग-अलग मत वाले विभिन्न दलों के नेताओं के बीच आम सहमति बनाना शायद उनके ही वश की बात थी। संसद के भीतर और बाहर अपने इसी राजनीतिक कौशल के कारण वह विपक्षी दलों के बीच भी आदर और सम्मान पाते थे।

राज्यसभा को एक ऐसे सदन के तौर पर जाना जाता है जो विभिन्न विषयों पर कहीं अधिक धीर-गंभीर होकर चिंतन-मनन करता है। लंबे समय तक राज्यसभा के सदस्य रहे अरुण जेटली की ख्याति एक धीर-गंभीर स्वभाव वाले राजनेता की ही थी, लेकिन वह अपनी विनोदप्रियता के लिए भी जाने जाते थे। वास्तव में इसीलिए उन्हें सुनना रुचिकर भी होता था और ज्ञानवर्द्धक भी। छात्र राजनीति से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले अरुण जेटली राजनीति के साथ ही विधि क्षेत्र की भी एक बड़ी हस्ती थे। वह जितने काबिल राजनेता थे उतने ही दक्ष वकील। इसके अलावा वह क्रिकेट प्रशासक के तौर पर भी जाने जाते थे और एक प्रखर बुद्धिजीवी के रूप में भी अपनी पहचान रखते थे। इसी कारण उनके प्रशंसक राजनीति से इतर क्षेत्र में भी हैं। यह सहज स्वाभाविक है कि 66 साल के अरुण जेटली के निधन को एक बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि देश के राजनीतिक जीवन में उन मूल्यों को महत्व मिले जिनके लिए वह जाने जाते थे।

सुशासन की राह

उत्तराखंड स्मार्ट राशनकार्ड के जरिये सुशासन की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा रहा है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सरकारी सस्ते खाद्यान्न की आपूर्ति कर रहे तंत्र में व्याप्त खामियों को दूर कर सुधार की मुहिम सराहनीय है। राशनकार्ड बनाने में फर्जीवाड़े की शिकायतों पर अंकुश लगाने को बीते वर्षों में काफी काम हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशनकार्ड को बनाने में काफी सावधानी बरती गई। इसके बाद राज्य खाद्य योजना के तहत भी ऐसा हुआ। उक्त दोनों योजनाओं को मिलाकर प्रदेश में 23 लाख से ज्यादा राशनकार्डधारक हैं। अब केंद्र सरकार की योजना राशनकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत एक परिवार एक राशनकार्ड पर उत्तराखंड अमल कर रहा है। इस योजना में बनने वाले राशनकार्ड स्मार्टकार्ड के रूप में बनेंगे। इन्हें आधार से लिंक किया जाएगा। साथ ही राशनकार्ड में दर्ज परिवार के प्रत्येक सदस्य को यूनिक नंबर दिया जाएगा। जाहिर है कि अब प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में किसी भी व्यक्ति के लिए एक से ज्यादा राशनकार्ड बनाना मुमकिन नहीं होगा। स्मार्टकार्ड योजना के अमल में आने पर सरकारी सस्ते खाद्यान्न और केरोसिन की कालाबाजारी पर स्वाभाविक रूप से रोक लगेगी। सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो अगले दो से तीन माह में उक्त स्मार्ट कार्ड उपभोक्ताओं को मिल जाएंगे। स्मार्ट कार्ड को आधार और बैंक खातों से लिंक करना है, लिहाजा जिलों में उपभोक्ताओं का नया डाटा जुटाया जाना है। विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को अपडेट जानकारी देने के लिए तय फॉर्मेट वाले प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इस मामले में विभाग को मुश्किलें भी आनी तय हैं। दरअसल, विभाग पर नए राशनकार्ड नहीं बनाने के आरोप भी लग रहे हैं। स्मार्ट कार्ड की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन है। दूरदराज पर्वतीय क्षेत्रों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में नेट कनेक्टिविटी, ग्रामीणों के आधार लिंक बैंक खातों और राशनकार्डों की समस्या बनी हुई है। सस्ता गल्ला दुकानों के कंप्यूटरीकरण की मुहिम भी चल रही है, लेकिन दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें अभी पुराने ढर्रे पर ही चल रही हैं। इस वजह से इन क्षेत्रों में लोगों के खातों में सरकारी खाद्यान्न के एवज में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से धन नहीं पहुंच पा रहा है। स्मार्ट कार्ड लागू करने से पहले इन दिक्कतों को दूर करना भी जरूरी है।

जांच एजेंसियों की जवाबदेही भी जरूरी

संजय गुप्त

यह जरूरी है कि जांच एजेंसियां चिदंबरम पर लगे आरोपों से संबंधित ऐसे साक्ष्य जुटाएं जो अदालत के समक्ष ठहर सकें

आखिरकार पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम सीबीआइ से बच नहीं सके। हालांकि उन्होंने सीबीआइ की गिरफ्त से बचने की तमाम कोशिश की, लेकिन अदालतों की ओर से कोई राहत न मिलने के कारण उन्हें नाकामी ही मिली। वह सीबीआइ की रिमांड में इसलिए हैं, क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने आइएनएक्स मीडिया में अनुचित तरीके से विदेशी निवेश में मदद की और इसका लाभ उनके बेटे कार्ति की बेनामी कंपनियों को मिला। आइएनएक्स मीडिया पीटर और इंद्राणी मुखर्जी की कंपनी थी। जब बेटी की हत्या के मामले में इंद्राणी मुखर्जी से पूछताछ हो रही थी तो यह पता चला कि चिदंबरम के दखल से ही आइएनएक्स मीडिया में निवेश को मंजूरी मिली थी। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड ने यह मंजूरी दी थी। मंजूरी करीब चार करोड़ रुपये की दी गई थी, लेकिन तीन सौ करोड़ रुपये से अधिक की राशि निवेश की गई। जांच एजेंसियों की मानें तो तय सीमा से अधिक निवेश करके काले धन को सफेद करने का काम किया गया। इसी मामले की जांच में सीबीआइ चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाह रही थी। अग्रिम जमानत मिलते रहने के कारण वह ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पा रही थी, लेकिन बीते दिनों जब दिल्ली उच्च न्यायलय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी तो वह भूमिगत हो गए। जब सीबीआइ चिदंबरम की तलाश कर रही थी तो वह कांग्रेस के दफ्तर में प्रकट हुए। वहां उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। जब तक सीबीआइ उन तक पहुंचती तब तक वह घर चले गए। आखिरकार सीबीआइ को उनके घर की दीवार फांदकर उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। इसके बाद सीबीआइ की विशेष अदालत ने उन्हें चार दिन के लिए रिमांड पर दे दिया।

चिदंबरम पूर्व केंद्रीय वित्त और गृह मंत्री ही नहीं, राज्यसभा सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। उनका इस तरह घपले-घोटाले की चपेट में आना और गिरफ्तार होना अप्रत्याशित है। एक कुशल प्रशासक और काबिल वकील की छवि वाले चिदंबरम ने जिस तरह जांच एजेंसियों से लुका-छिपा की और जिन हालात में वह गिरफ्तार हुए उसने सारे देश का ध्यान आकर्षित किया। कांग्रेसी नेता उनका बचाव करते हुए सीबीआइ की कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, लेकिन वह जिस तरह लगभग 27 घंटे तक सीबीआइ को चकमा देते रहे वह कई सवाल खड़े करता है। इस घटनाक्रम में सबसे ज्यादा सवाल इसे लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस करना जरूरी क्यों समझा?

वैसे एक सवाल यह भी है कि सीबीआइ 27 घंटे तक चिदंबरम को ढूंढ क्यों नहीं पाई? सीबीआइ के बाद ईडी भी चिदंबरम से पूछताछ करना चाह रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनकी याचिका का निस्तारण होने तक ईडी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। पता नहीं आइएनएक्स मीडिया मामले का सच क्या है, लेकिन यह तो जरूरी है ही कि जांच एजेंसियां चिदंबरम पर लगे आरोपों से संबंधित ऐसे साक्ष्य जुटाएं जो अदालत के समक्ष ठहर सकें। यह इसलिए, क्योंकि जांच एजेंसियां इस आरोप से दो-चार होती ही रहती हैं कि वे राजनीतिक दबाव में काम करती हैं। स्वाभाविक तौर पर चिदंबरम के मामले में भी ऐसे आरोप लगे हैं। कांग्रेस केवल चिदंबरम को केवल तंग करने का आरोप ही नहीं लगा रही है, बल्कि उन्हें क्लीनचिट भी दे रही है। बेहतर हो कि कांग्रेस इस पर ध्यान दे कि वह खुद अदालत का काम नहीं कर सकती। उसे इससे भी परिचित होना चाहिए कि जब वह सत्ता में थी तब भी सीबीआइ के दुरुपयोग के आरोप लगते थे। खुद सुप्रीम कोर्ट ने उसे पिंजरे में कैद तोता बताया था। यह भी नहीं भूला जा सकता कि सीबीआइ एक समय किस तरह गुजरात के तत्कालीन गृहमंत्री अमित शाह के पीछे पड़ी और उन्हें गिरफ्तार करके ही मानी थी।

भारत में राजनीतिक भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। सभी इससे अवगत हैं कि संप्रग सरकार में किस तरह एक के बाद एक घोटाले हुए। आइएनएक्स मीडिया मामला भी उसी दौर का है। हैरानी की बात यह है कि तमाम राजनीतिक घपलों-घोटालों के बावजूद हमारी शीर्ष जांच एजेंसियां बहुत कम लोगों को सजा दिला पाने में कामयाब हो पाती हैं। जो मामला जितने बड़े नेता से जुड़ा होता है उसमें जांच एजेंसियों की सफलता की दर उतनी ही कम रहती है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि नेताओं और नौकरशाहों की साठगांठ के कारण ही भ्रष्टाचार के बड़े मामलों की तह तक नहीं पहुंचा जाता। एक तो नेताओं से जुड़े मामलों की जांच में लंबा समय लगता है और दूसरे, ऐसे सुबूत नहीं जुटाए जा पाते जो अदालत में टिक सकें। 2जी मामले में ऐसा ही हुआ था जिसमें ए राजा भी आरोपित थे। इस मामले में सीबीआइ की ओर से जुटाए गए सारे सुबूत अदालत ने सिरे से खारिज कर दिए थे।

यदि भारत में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना है तो हर स्तर पर जांच एजेंसियों को सक्षम बनाना होगा। इसी के साथ उन्हें राजनीतिक दबाव से भी मुक्त रखना पड़ेगा। इसके लिए सरकारों के साथ जांच एजेंसियों को भी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए सक्रिय होना होगा। चाहे चिदंबरम से जुड़ा आइएनएक्स मीडिया मामला हो या फिर राहुल-सोनिया गांधी से संबंधित नेशनल हेराल्ड मामला अथवा अन्य नेताओं से जुड़े और कई मामले-इन सबका निस्तारण यथाशीघ्र होना चाहिए। जब नेताओं या फिर नौकरशाहों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में समय रहते दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो पाता तो जांच एजेंसियों की बदनामी होने के साथ ही सरकारों की भी किरकिरी होती है।

फिलहाल किसी के लिए यह कहना कठिन है कि चिदंबरम के मामले का निस्तारण कब और कैसे होगा, लेकिन यह ठीक नहीं कि जब किसी नेता के खिलाफ गंभीर आरोप लगते हैं तो उनके साथियों-समर्थकों की ओर से यह माहौल बनाया जाता है कि उन्हें राजनीतिक कारणों से परेशान किया जा रहा है। खुद आरोपों के घेरे में खड़े नेता भी अपने को पाक-साफ बताते हैं। इसके विपरीत जब कोई कारोबारी किसी मुश्किल में फंसता है तो उसे तत्काल ही चोर-लुटेरा करार दिया जाता है। साधारण मामला होने पर भी उसे जमानत तक नहीं मिलती। आखिर जो तमाम राहत-रियायत नेताओं को मिल जाती है वह कारोबारियों को क्यों नहीं मिलती? वास्तव में यह वह सवाल है जो यह बयान करता है कि अपने देश में अलग-अलग लोगों के लिए किस तरह भिन्न-भिन्न मापदंड अपना लिए गए हैं। इन दोहरे मापदंडों का परित्याग किया जाना चाहिए। इसलिए और भी, क्योंकि प्रधानमंत्री वेल्थ क्रिएटर के प्रति सम्मान का भाव विकसित करने की जरूरत जता रहे हैं। इस जरूरत की पूर्ति तभी होगी जब जांच एजेंसियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। यह जवाबदेही नेताओं के मामले में भी तय होनी चाहिए और कारोबारियों के साथ-साथ आम लोगों के मामलों में भी।

response@jagran.com

अवधेश राजपूत

सरल हृदय वाले विराट राजनेता

भूपेंद्र यादव

जटिल से जटिल कानूनी-संवैधानिक विषयों को सरलता से व्यक्त करने में अरुण जेटली का कोई सानी नहीं था

अरुण जेटली के निधन की सूचना मन को व्यथित करने वाली है। वह इतनी जल्दी चले जाएंगे, यह विश्वास नहीं होता। उनका मिलनसार स्वाभाव कभी भुलाया नहीं जा सकता। अपने जीवन के अंतिम समय में बीमारी से जूझते हुए उन्होंने कभी इसे महसूस नहीं होने दिया। वह लगातार सक्रिय रहे। उनका कद बहुत बड़ा था, किंतु उनका हृदय उतना ही सरल था। वह प्रखर व्यक्तित्व के धनी थे, किंतु सहजता में उनका कोई सानी नहीं था। उनके साथ अनेक अवसरों पर लंबे समय तक काम करते हुए मैंने यह अनुभव किया कि जो भी विषय उनके समक्ष रखा जाता उसे ध्यानपूर्वक समझना और बारीकी से उसे परखना उनकी विशेषता थी। अरुण जेटली एक उत्कृष्ट अधिवक्ता थे, लेकिन उनके तर्कों में केवल कानूनी दृष्टि नहीं, बल्कि मानवीयता और संवेदनशीलता का भाव उभर कर आता था। मानवीयता का दृष्टिकोण उनके जीवन का एक बहुत बड़ा पक्ष रहा। उनका यही दृष्टिकोण उन्हें एक महान व्यक्तित्व बनाता है।

अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत दिल्ली छात्र संघ के एक नेता के रूप में करने वाले अरुण जेटली का छात्र-जीवन लोकतंत्र को बचाने के लिए आपातकाल के विरुद्ध नेतृत्व करने वाले छात्र नेता के रूप में भी याद किया जाएगा। लोकतंत्र के बुनियादी मूल्यों में उनका अटूट विश्वास इसी से पता चलता है कि आपातकाल के विरुद्ध उन्होंने देश के सबसे बड़े छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। इस संघर्ष के दौरान वह जेल भी गए और वहीं से उन्होंने वकालत की परीक्षा भी दी। उनके जीवन का यह संघर्षपूर्ण, किंतु महत्वपूर्ण पड़ाव दिखाता है कि वह कैसी अद्भुत मेधाशक्ति से संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने वकालत के दौरान कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अनेक प्रकार के जटिल से जटिल संवैधानिक विषयों को भी वह बहुत बेहतर ढंग से स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करते थे।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकारों में उन्हें जो दायित्व मिले, उनका उन्होंने सफलतापूर्वक निर्वहन किया। देश में ग्राम न्यायालय का विषय हो, राज्यसभा के मतदान में सुधार हो या फास्ट ट्रैक न्यायालयों की बात हो, वाजपेयी सरकार में विधि मंत्री रहते हुए अरुण जेटली द्वारा किए गए ये कार्य हमेशा याद किए जाएंगे। मोदी सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए जीएसटी जैसे बड़े आर्थिक सुधार और आईबीसी कानून के पीछे अरुण जेटली की दूरदर्शिता थी। मेरे लिए यह अविस्मरणीय है कि इन दोनों ही कार्यों से संबंधित संसद की समितियों का अध्यक्ष बनने का उन्होंने मुझे अवसर दिया। साथ ही, जब भी इनमें किसी प्रकार के कानूनी पक्ष को लेकर कभी कोई समस्या हमारे सामने आई तो वह उसका भी समाधान किया करते थे। संविधान और कानून का गहन अध्ययन रखने वाले अरुण जेटली नए विचारों के प्रति सदैव उदार रहे। यदि उन्हें कोई सुझाव दिया जाता तो उसको भी वह खुले दिल से स्वीकार करते थे।

संसद में एक कुशल और सफल सांसद के रूप में उनका लंबा कार्यकाल रहा। वह सर्वश्रेष्ठ सांसद भी रहे। मित्रों के सुख-दुःख और समस्याओं में काम आना अरुण जेटली के स्वभाव की विशेषता थी। संकट के ऐसे अनेक क्षणों में मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा जब वह मित्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने निजी कार्यों की भी चिंता नहीं किया करते थे। शायद यही कारण था कि उनके संबंध और संपर्क सामान्य नेता से लेकर समाज के विशिष्ट वर्ग तक सबसे समान रूप से थे। राजनीतिक जीवन में भी वह सबसे मिल-जुलकर तथा बेहतर संबंधों के साथ रहने में विश्वास रखते थे। विभिन्न राजनीतिक दलों से संवाद करना और उनके नेताओं से संबंध रखना जेटली की कार्यशैली की विशेष खासियत रही।

जेटली की वक्तृत्व क्षमता भी अद्भुत थी। संसद में अनेक विषयों पर उनके दिए भाषण सहेजने योग्य हैं। विविध विषयों पर ब्लॉग लिखना, सोशल मीडिया के उपयोग से संवाद कायम करना, सामाजिक विषयों की जानकारी देना, जटिल कानूनी विषयों को सरल ढंग से लोगों को समझाना उनके संवादप्रिय व्यक्तित्व को रेखांकित करने वाला पक्ष है। उनके साथ काम करने का जब भी अवसर मिला, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इतनी बड़ी शख्सियत के साथ काम कर रहे हैं। अगर कभी कोई गलती उनकी नजर में आती तो उसे बताने के साथ-साथ सुधारने का अवसर भी देते थे। जब भी कोई बात उन्हें अच्छी लगती थी तो वह प्रोत्साहित करते और कमियों के विषय में सुझाव एवं सलाह भी देते। उनके ज्ञान क्षेत्र का विस्तार अनेक बार आश्चर्यचकित कर देता था। उनका व्यापक अध्ययन और विविध विषयों का विश्लेषण इतना गहन था कि उनके साथ चर्चा के दौरान ऐसा लगता मानों वह अभी-अभी एक किताब पढ़कर उठे हों।

इतने वरिष्ठ होने के बावजूद वह इतने मित्रवत और मिलनसार थे कि कभी लगा ही नहीं कि मन में ऐसी कोई बात है जो जेटली जी से नहीं कह सकते। संसद में वह इतने सहज रहा करते थे कि बजट पेश करने के बाद सबको अपने कमरे में बुलाकर हंसी-मजाक करते और खाना खिलाते। उनके सहज व्यवहार से ऐसा लगता ही नहीं था कि वह अभी-अभी बजट पेश करके आए हैं। उनके निधन से मैंने और मेरे जैसे अनेक लोगों ने विश्वास के साथ आगे बढ़ाने वाला एक ऐसा बड़ा भाई खो दिया जिसने हमेशा सही दिशा दिखाई। अपने राजनीतिक जीवन में वह अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए आम जनता और प्रबुद्ध वर्ग को मिलाने के सेतु की तरह रहे। उनका निधन भारतीय जनता पार्टी और उसके विचार के साथ-साथ देश की राजनीति के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है।

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सार्थक हो संवाद

आम बोलचाल की भाषा में अक्सर यह शब्द प्रयोग किया जाता है कि मेरे कहने का 'वह मतलब' नहीं था। इसका तात्पर्य होता है कि हमने कहा कुछ और है, किंतु समझने वालों ने उसका अर्थ कुछ और ही समझ लिया है। जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह शब्दों के भी अनेक अर्थ होते हैं। कहने वाला किसी बात को किसी रूप में कहना चाहता है और सुनने वाले उसे किसी और रूप में ग्रहण कर लेते हैं। इससे सामान्य सी चर्चा भी बहस का रूप धारण कर लेती है। बहस की स्थिति के चलते आपसी व्यवहार पर प्रतिकूल असर तक देखने में आता है। भ्रम की स्थिति की जिम्मेदार वह समझ होती है जो किसी बात को कहने और उस बात को समझने वाले व्यक्ति पर निर्भर करती है।

वर्तमान समय में ऐसे अनेक मामले देखने में आते हैं, क्योंकि आज के समय में संवाद प्रत्यक्ष के बजाय आभासी रूप में अधिक किया जाता है। आधुनिक संचार माध्यमों जैसे सोशल मीडिया इत्यादि पर प्रायः भ्रम की ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। शब्दों के उपयोग करने और समझने वाले पर निर्भर करता है कि उनमें शब्दों के उपयोग करने और समझने की क्षमता कैसी है। संचार के इस आभासी माध्यम के चलते ऐसी स्थितियां आम हैं, इसलिए ऐसे किसी संवाद में किसी सोच का निर्माण करने के पूर्व सावधानी बरतनी आवश्यक है।

क्षणिक आवेग में हम जब किसी कथन पर अपने मस्तिष्क में एक धारणा बनाकर तटस्थ हो जाते हैं और उस आधार पर ही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तब विचारों में गतिरोध पैदा होता है। द्विपक्षीय संवाद का एक पक्ष पूर्व में तो दूसरा पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर हो जाता है। चर्चा के अंत में जो निष्कर्ष निकलता है उससे दोनों ही पक्षों को कुछ सार्थक हासिल नहीं हो पाता। जब जीवन में आधुनिकता ने इतना प्रवेश कर लिया है तो आभासी दुनिया के इस मोह से हम दूर नहीं रह सकते। ऐसे में इतना कर ही सकते हैं कि जब भी मतभेद की स्थिति हो तो प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने पर बल दें ताकि मनभेद की स्थिति से बचा जा सके।

सौरभ जैन

बृहस्पति के चंद्रमा पर खास अभियान

मुकुल व्यास

यूरोपा पर जाने वाले यान में लगे नौ उपकरण उसके चुंबकीय क्षेत्र, तापमान और तमाम अन्य खासियतों का विश्लेषण करेंगे

नासा ने बृहस्पति के रहस्यमय बर्फीले चंद्रमा यूरोपा की पड़ताल के लिए अपने महत्वाकांक्षी 'यूरोप क्लिपर' मिशन की तैयारी शुरू कर दी है। मिशन के समक्ष जो सरकारी बाधाएं थीं वे अब दूर हो चुकी हैं। स्वतंत्र समीक्षा में पास होने के बाद ही अंतिम डिजाइन और निर्माण की अनुमति मिलती है। अब नासा ने अपनी टीम को इस मिशन के लिए हरी झंडी दे दी है। यूरोपा के लिए प्रस्तावित अंतरिक्ष यान के डिजाइन और निर्माण का काम शीघ्र आरंभ होगा और अगले कुछ वर्षों में मिशन के पूरी तरह से तैयार हो जाने की उम्मीद है।

नासा ने पहले स्पेस लॉन्च सिस्टम (एसएलएस) रॉकेट से अंतरिक्ष यान को भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन इसके निर्माण में हो रहे विलंब को देखते हुए उसे मिशन के लिए वैकल्पिक रॉकेट ढूंढना पड़ेगा। नासा ने पहले वर्ष 2023 या 2025 में यूरोपा मिशन भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन तब तक एसएलएस रॉकेट के तैयार होने की उम्मीद नहीं है। अब किसी छोटे व्यावसायिक रॉकेट के इस्तेमाल की बात चल रही है। वैसे नासा ने अभी तक क्लिपर मिशन भेजने की कोई तारीख निर्धारित नहीं की है।

1970 के दशक के उत्तरार्ध में नासा के वॉयेजर यानों ने यूरोपा के बगल से गुजरते हुए उसके कई फोटो भेजे थे। तभी से यह बर्फीला चंद्रमा शोधकर्ताओंका ध्यान आकृष्ट कर रहा है। वैज्ञानिकों ने इस पिंड का गहराई से अध्ययन किया है और इसकी अनेक विशेषताओं का पता लगाया है। वैज्ञानिकों का खयाल है कि यूरोपा की बर्फीली चादर की मोटाई 10 से 15 किलोमीटर तक हो सकती है। इस चंद्रमा की सतह पर गहरी धारियां हैं जिनके आधार पर यह अटकल लगाई गई कि सतह के नीचे तरल जल का समुद्र मौजूद है। इस समुद्र की गहराई 60 से 150 किलोमीटर तक हो सकती है। यदि बर्फीली सतह के नीचे सचमुच तरल जल मौजूद है तो यूरोपा पर मौजूद पानी की मात्रा पृथ्वी के सारे समुद्रों में जमा कुल पानी से कई गुणा अधिक हो सकती है। बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न होने वाली ज्वारीय ऊष्मा यूरोपा के समुद्र को तरल अवस्था में रख सकती है जिससे वहां जीवन को पनपने का मौका मिल सकता है। वैसे नासा का जूनो अंतरिक्ष यान इस समय बृहस्पति सिस्टम की छानबीन कर रहा है, लेकिन इस यान को बृहस्पति के चंद्रमाओं के अध्ययन के उद्देश्य से निर्मित नहीं किया गया है।

यूरोपा क्लिपर पहला मिशन है जो पृथ्वी के चंद्रमा को छोड़ सौरमंडल के किसी और चंद्रमा पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। यूरोपा क्लिपर चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरेगा, लेकिन 40 बार उसके नजदीक से गुजरेगा। यान पर लगे नौ उपकरण उसके चुंबकीय क्षेत्र, तापमान और अन्य विशेषताओं का विश्लेषण करेंगे। यूरोपा बीच-बीच में अंतरिक्ष की तरफ पानी के फव्वारे छोड़ता रहता है। ये फव्वारे सतह से 160 किलोमीटर तक ऊपर जाते हैं। यदि यूरोपा क्लिपर इन फव्वारों से गुजरने में कामयाब हो जाता है तो वह जल की रासायनिक संरचना का भी विश्लेषण कर सकता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

दूर हुई वीरानी

अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी के नेतृत्व की वापसी के बाद फिर से हलचल दिखने लगी है। लंबे समय से वीरान दिखने वाले कांग्रेस मुख्यालय 24, अकबर रोड में बीते दस दिनों से कार्यकर्ताओं की आवाजाही बढ़ गई है। राजीव गांधी की जयंती से जुड़े एक कार्यक्रम से कुछ दिन पहले ही नहीं, बल्कि बाद में भी सैकड़ों की तादाद में देश भर से आते कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सिलसिले को देखकर पार्टी के कुछ नेता भी हैरान दिखे। कुछ सालों से लगभग वीरान दिखने वाले मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की चहल-पहल फिर से लौटने की वजह जब सामने आई तो नेतृत्व के नजरिये का फर्क सामने आया। दरअसल राहुल गांधी के दौर में पार्टी कार्यक्रमों के न्योते बांटने से लेकर अहम बैठकों के दौर अमूमन रकाबगंज रोड के वार रूम से होते थे जहां के दरवाजे कार्यकर्ताओं के लिए खुलते ही नहीं थे। सोनिया गांधी की वापसी के साथ ही ऐसी गतिविधियां एक बार फिर पार्टी मुख्यालय लौट आई हैं। इससे जहां कार्यकर्ता न केवल आने लगे हैं, बल्कि अपने-अपने सूबे के नेताओं और प्रभारियों से रूबरू भी होने लगे हैं। बहरहाल कांग्रेस को अपने सियासी रंग में लौटने में भले ही लंबा वक्त लगेगा, मगर पार्टी मुख्यालय में चहल-पहल की वापसी का आगाज तो हो ही गया है।

राजरंग

पानी भी टपका, गाज भी गिरी

पिछले दिनो रांची से फोटो और विजुअल के साथ एक खबर चली जिसमें एक लोको पायलट को छत से टपकते बरसाती पानी से बचाव के उपक्रम में छतरी लेकर ट्रेन चलाते दिखाया गया था। खबर सही थी, लेकिन रेलवे ने फिर भी बिना किसी ठोस तर्क के न सिर्फ उसका खंडन किया, बल्कि उस लोको पायलट को कार्रवाई का नोटिस भी थमा दिया कि तुमने छाता लेकर फोटो क्यों खिंचवाई और रेलवे की खिल्ली क्यों उड़वाई। यही नहीं, उस बेचारे पर यह इल्जाम भी लगाया गया है कि उसने ट्रेन ले जाने से पहले टपकती छत के बारे में उस रोज शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई थी। जबकि इसका जवाब खबर में ही मौजूद है जिसमें लिखा है कि लोको पायलट जब अधिकारियों से शिकायत करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती और उन्हें वैसे ही ट्रेन चलाने को कहा जाता है। गजब है भारतीय रेल।

नाकाम एजेंसियां

देश की राजधानी दिल्ली में सभी जांच और खुफिया एजेंसियों की नाक के नीचे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम लगभग 27 घंटे तक भूमिगत रहे और किसी को कानों-कान कोई खबर तक नहीं लगी। चिदंबरम को ढूंढ पाने में जांच एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों की बड़ी नाकामी गृह मंत्रालय के गलियारों में किसी के गले नहीं उतर रही है। खुफिया एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुद कहा कि एक जाने-माने व्यक्ति को खोज पाने में इस तरह की नाकामी सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता पर एक बड़ा सवालिया निशान है। बात गिरफ्तार करने या नहीं करने या फिर जहां भी चिदंबरम छुपे थे, वहां छापा मारने या न मारने की नहीं है। बात है कि एजेंसियों को चिदंबरम के छिपे होने की जगह की जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक चिदंबरम खुद कांग्रेस मुख्यालय में अवतरित नहीं हुए एजेंसियों को उनकी कोई भनक तक नहीं थी।

योजना आयोग की राह पर नीति आयोग

सरकार का थिंक टैंक होने का लक्ष्य लेकर चलने वाला नीति आयोग भी अपने पूर्ववर्ती योजना आयोग के रास्ते चलने लगा है। कम से कम सेवानिवृत्त नौकरशाहों के मामले में तो ऐसा ही हो रहा है। सरकार की सेवा समाप्त करने वाले नौकरशाह एक-एक करके नीति आयोग में जगह पाने लगे हैं। ताजा नियुक्ति कैबिनेट सचिव के पद से रिटायर हो रहे वरिष्ठ नौकरशाह पीके सिन्हा की है। इससे पहले रतन वट्टल भी रिटायरमेंट के बाद नीति आयोग में ठौर पा चुके हैं। इन नियुक्तियों को लेकर आजकल आयोग में ही ये चर्चाएं आम हो गई हैं कि देश में क्या विशेषज्ञों की इतनी कमी हो गई है कि सदस्य के लिए नौकरशाही का ही भरोसा रह गया है। नीति आयोग को विभिन्न क्षेत्रों में विकास संबंधी योजनाएं बनाने के लिए सरकार के थिंक टैंक के तौर पर विकसित किया जाना था जिनमें तमाम क्षेत्रों के विशेषज्ञों के लिए संभावनाएं थीं, लेकिन अब आयोग के अंदर ही इस तरह की नियुक्तियों पर चर्चा शुरू हो गई है।

स्पष्टीकरण

कल के अंक में **नए कश्मीर का उदय** शीर्षक से प्रकाशित लेख में जिस सिकंदर का जिक्र है, वह वस्तुतः सिकंदर शाह को लेकर है, जिसे सिकंदर बुतशिकन भी कहा जाता था। -संपादक

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।